पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 28, अंक 265 नवंबर 2025

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

आश्वस्त

वर्ष : 28 अंक 265
नवम्बर 2025

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/09510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ.बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2	भारत-कनाड़ा के बीच बिगड़ते कूटनीतिक रिश्ते	डॉ. सुशील कुमार यादव असिस्टेंट प्रोफेसर	04
3	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की पत्रकारिता : **सामाजिक न्याय और सुधार की आवाज**	डॉ. मिली सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रेखा सिंह सहायक प्रोफेसर	06
4	उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की स्थिति (विशेष अध्ययनः परिशिष्टि/गिरिराज किशोर)	ज्योति कुमारी शोधार्थी (हिन्दी विभाग) डॉ. रवि रंजन कुमार सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)	08
5	Dr. Babasaheb Ambedkar and Linguistic Equality in India	Dr. Kishorkumar G. Gaikawad Asst. Professor	10
6	"Caste and Identity Politics :Challenges and Opportunities for Social Justice in the Preview of the Supreme Court of India as Good Governance"	Mr. Parminder First Author Dr. Manjit Singh Second Author	14
7	A Literature review on the Impact of Surya Namaskar on Athlete's Health : Physical Physiological and Psychological prespectives	Dr. Himani Malhotra	17
8	Reconstructing Historical Narratives through Biopics : A Study on the Film Dr. Babasahed Ambedkar	Fathima Sullami T.A. Assistant Professor	21
9	समाचार : मूल निवासी सभ्यता संघ द्वारा सांची, मध्यप्रदेश में आयोजित तीन दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय महासंगीत का सफल आयोजन सम्पन्न	प्रस्तुति - शील बोधि समन्वयक, भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय संगीति	26

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

भारत के संविधान ने हाल ही में 75 वर्ष पूरे किए। यह अवसर हमारे संविधान–निर्माताओं की दूरदर्शिता और संविधान के अद्भुत स्थायित्व का प्रतीक है।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान प्रारूप समिति की नियुक्ति की जिसमें डॉ. अम्बेडकर को न केवल मनोनीत किया बल्कि उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी चुना गया।

बाबा साहेब ने संविधान का प्रारूप प्रथम वाचन के लिये पेश करते हुए 4 नवम्बर, 1948 को अपने भाषण में कहा–''कोई भी संविधान संपूर्ण नहीं। संविधान जैसा कि प्रारूप समिति ने बनाया है। इस देश में शुरूआत करने के लिये काफी उपयुक्त है। मेरे विचार में यह काम चलाने लायक है। युद्ध और शांति दोनों अवसरों में यह देश को एक साथ रखने के लिये काफी सुदृढ़ है। वास्तव में, यदि मैं कहूँ–नये संविधान में परिस्थितियाँ बिगड़े तो कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान बुरा है बल्कि हमें यह कहना पड़ेगा कि आदमी दुष्ट था।''

प्रारूप के तीसरे वाचन के समय डॉ. अम्बेडकर ने 25 नवम्बर 1949 को सभा में कहा–''संविधान सभा में मैं क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिये। इससे अधिक और मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ आने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कोई कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा ने जब मुझे प्रारूप समिति में नियुक्त किया तब मुझे आश्चर्य हुआ ही परन्तु जब प्रारूप समिति ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो मुझे आश्चर्य का धक्का–सा लगा। संविधान सभा और प्रारूप समिति ने मुझ पर इतना विश्वास करके मुझसे यह काम सम्पन्न करवाया, उसके लिये मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।'' डॉ. अम्बेडकर साहेब ने बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में यह और कहा–''मुझे चिंता इस बात की है कि भारत ने पहले अपनी स्वतंत्रता ही नहीं खोई बल्कि वह अपने ही लोगों के विश्वासघात और बदमाशी से खो गई थी। देश एक समय स्वतंत्र था परंतु जो देश एक बार अपनी स्वतंत्रता खो बैठा, दूसरी बार भी खो सकता है।'' क्या इतिहास अपने को दोहराएगा? इस बात से मेरा मन चिंताग्रस्त है। जातियों और पंथों के रूप में अपने पुराने शत्रुओं के अलावा हमारे देश में अनेक दल हैं जो विरोधी विचारों तथा मार्गों का पोषण करते हैं। इसलिए संकुचित पंथ या पक्ष को प्रधानता दी गई तो देश फिर एक बार मुसीबतों में फंस जाएगा। अतः हमें दृढ़तापूर्वक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा रक्त की अंतिम बूंद तक करनी चाहिए।''

यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति संवैधानिक ढंग से करनी चाहिए। अन्य हिंसात्मक तरीकों से नहीं।

स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व भाव के आधार पर अधिष्ठित सामाजिक जीवन ही लोकतंत्र कहलाता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता का अर्थ बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व का होता है। 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीति में समानता मिलेगी परंतु सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी। भारतीय समाज में समानता का अभाव है। हमें इस विषमता का शीघ्रता से अंत करना चाहिए अन्यथा विषमता से बुरी तरह पीड़ित लोग, इस संविधान सभा द्वारा बड़े परिश्रम से खड़े किये गये लोकतंत्र के महल को मिट्टी में मिला देंगे। अन्त में डॉ. अम्बेडकर ने सभी भारतीयों से अपील की कि वे सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ में एक राष्ट्र बनें और जातियों का निषेध करें जिनके कारण हम अवनति की स्थिति में न गिरें। परस्पर जातिगत भेदभावों को भुलाकर हमें संगठित रहना चाहिए। जिस संविधान में हमने ''जनता के लिये, जनता का और जनता द्वारा राज्य–तत्व अन्तर्भूत किया है वह संविधान दीर्घकाल तक बना रहे, ऐसा यदि हम सब चाहते हैं तो हमें देश के संकटों को समझने में और उनका निराकरण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। सभी नागरिकों को देश की सेवा करने का यही मार्ग अपनाना चाहिए।''

जय भीम, जय भारत, जय संविधान

– डॉ. तारा परमार

भारत-कनाडा के बीच बिगड़ते कूटनीतिक रिश्ते

– डॉ. सुशील कुमार यादव
असिस्टेंट प्रोफेसर

सारांश–विदेश नीति मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की बचकाना हरकतों पर भारत की प्रतिक्रिया सहज थी। उन्होंने कहा, भारत पर लगाए गये गलत आरोपों से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़े हैं। भारतीय विदेश नीति के विशेषज्ञों को लगता है कि कनाडा शायद जानबूझकर तनाव बढ़ाना चाहता है। इसी संदर्भ में भारत की रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने कहा, कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से उपजे विवाद पर भारतीय राजनयिकों की कनाडा से वापसी भारत सरकार का कड़ा कदम है। इसने पूरी दुनियाँ को दिखा दिया है कि भारत इस तरह की बेजा हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा यह भारत के एक सशक्त देश के तौर पर उभरने का संकेत भी है। उन्होंने यह भी कहा कि– यह संदेश है कि यदि कोई भारत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा भारत के विरुद्ध सबूत न दे पाने को अशोभनीय बताया। कनाडा में भारत के राजदूत रह चुके के.पी. फेबियन ने रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे की बात से सहमति जताते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कनाडा जानबूझकर तनाव बढ़ाना चाहता है। हाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच गंभीर कूटनीतिक कार्यवाही दृष्टिगोचर हुई और दोनों देशों के मध्य संबंधों को लेकर विश्वास में कमी आई है।

मूलशब्द–भारत–कनाडा, विदेश नीति, प्रवासी, खालिस्तानी, अलगाववादी, कूटनीतिक, आतंकवादी, राजनयिक, अन्तर्राष्ट्रीय, सुरक्षा आदि।

प्रस्तावना–कनाडा और भारत के बीच उन्नीसवीं सदी से द्विपक्षीय सम्बन्ध रहे हैं। दोनों ही देश राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं और दुनियाँ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी –20 का सदस्य देश भी है। उन्नीसवीं सदी से ही भारत– कनाडा के बीच अच्छे सम्बन्ध रहे हैं और भारतीय नागरिक कनाडा जाकर विविध प्रकार की नौकरियों में कार्य करते रहे हैं। हमारा देश भारत, भारतीय प्रवासियों के साथ कनाडा में आप्रवासन के लिए एक प्रमुख देश बन गया। जब भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ तब दोनों देशों के बीच सम्बन्ध और भी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़े। कनाडा और भारत सन् 1990 के दशक में एक दूसरे के साथ व्यापारिक सौदों, द्विपक्षीय यात्राओं और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के हितों को बढ़ावा दिया। वैसे तो भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बहुत व्यापक रहे हैं, लेकिन सन् 1998 ई. में भारत द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण करने के बाद कनाडा और भारत के बीच रिश्ते कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गये हालाकि अतिशीघ्र दोनों देशों में सम्बन्धों में सुधार भी हो गया। वर्तमान में कनाडा और भारत के बीच सम्बन्ध खालिस्तानी आन्दोलन से जुड़े सिख अलगाववादियों द्वारा भारत में एक स्वतंत्र सिख पंजाबी राष्ट्र–राज्य की मांग किए जाने के कारण तनावपूर्ण हो गए हैं।

कनाडा ने खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाये है जब कि भारत सरकार ने यह दावा किया है कि कनाडा झूठे आरोप भारत पर लगा रहा है और कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। इस पर कनाडा का तर्क है कि खुफिया सूचना द्वारा उसे जानकारी मिली है कि इस घटना में भारत का हाथ है। जब कि भारत कनाडा के तर्क को सिरे से खारिज करता है और कहता है कि यह बेबुनियाद है। इन्हीं कारणों से वर्तमान अक्टूबर 2024 में कनाडा और भारत ने एक–दूसरे के राजनयिकों को अपने–अपने देशों से पुनः निष्कासित कर दिया है, और दोनों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

भारत कनाडा के बीच सम्बन्धों को लेकर बढ़ते विवाद से यही प्रतीत होता है कि एक नेता (ट्रूडो) की कूटनीतिक अदूरदर्शिता से दोनों देशों के बीच सम्बन्ध खतरनाक मोड़ पर पहुँच चुके हैं। भारत को अपने

उच्चायुक्त सहित अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला इसलिए करना पड़ा, क्यों कि कनाडा की ट्रूडो सरकार से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त सहित कुछ अन्य राजनयिकों की कथित लिप्तता की जाँच की जरूरत जताई थी। ट्रूडो की कनाडा सरकार ने इसके पहले भी अपने यहाँ पल रहे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराने की हास्यास्पद कोशिश की थी। उस समय भी भारत सरकार ने अपने कठोर रवैये का परिचय दिया था और कनाडा के लिए वीजा सेवा रोक दी थी। लगता है कि कनाडा सरकार नये सिरे से खालिस्तानियों को खुश करने में जुट गई है। खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो निरन्तर प्रयास कर रहे हैं, न केवल भारत से सम्बन्ध खराब कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकियों का गढ़ बनाने में लगे हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस कनाडाई विदूषक के साथ पूर्वी एशियाई देशों के सम्मेलन 21 सितम्बर 2024 को लाओस के वियनतियाने में संक्षिप्त मुलाकात की थी। मोदी ने कहा कि दुनियाँ के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों का सबसे नकरात्मक असर वैश्विक दक्षिण के देशों पर पड़ रहा है इसलिए अतिशीघ्र शांति व स्थिरता बहाल की जानी चाहिए। मोदी जी ने कहा, मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ, मैंने बार– बार कहा है, कि यह युद्ध का युग नहीं है, समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। वैश्विक युद्धों की वजह से जब पूरी दुनियाँ में अनिश्चितता है। ऐसे में पूर्वी एशियाई देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना कूटनीतिक लिहाज से तो अहम है ही साथ ही साथ हिंद–प्रशांत क्षेत्र की स्थितियों को लेकर भारत की गंभीरता को भी दर्शाता है। कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो को यह समझना ही होगा कि कूटनीतिक रिश्ते परिपक्वता की माँग करते हैं। मध्य अक्टूबर 2024 में भारत ने स्पष्ट कहा कि कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की पिछले वर्ष हुई हत्या मामले में अब तक एक भी पुख्ता सुबूत नहीं दिया है, जिसे लेकर वो भारत पर झूठा आरोप लगा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मंचों पर भी भारत का रुख सदैव से इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि आतंकबाद व हिंसा पर कार्रवाई सियासी सहूलियत से नहीं होनी चाहिए। दो लोकतांत्रिक देशों के मध्य कूटनीतिक रिश्ते परिपक्वता की माँग करते हैं।

निष्कर्षत : मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कनाडा में रहने वाले सभी भारतीय समुदायों को सावधान रहना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वह इन बिगड़ते हुए हालात में कनाडा सरकार के प्रति सतर्क रहे क्यों कि ट्रूडो की कूटनीतिक अदूरदर्शिता से दोनों देशों के वर्तमान सम्बन्ध खतरनाक मोड़ पर पहुँच गये है। ऐसी परिस्थितियों में भारत को अपने पड़ोसी देशों से भी सतर्क रहना होगा क्यों कि वे भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बढ़ती हुई साख से भी परेशान है और चिंतित हैं।

– **डॉ. सुशील कुमार यादव**
असिस्टेंट प्रोफेसर, सैन्य अध्ययन विभाग
के.जी. के.पी.जी. कॉलेज
मुरादाबाद (उ.प्र.) मो.–7522842862

संदर्भ :

1. डॉ.वी.एल. फड़ियां : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
2. राम सूरत पाण्डेय : राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
3. अमर उजाला : 12 अक्टूबर 2024
4. अमर उजाला (प्रवाह) : 14 अक्टूबर 2024
5. दैनिक जागरण (संपादकीय) : 15 अक्टूबर 2024
6. अमर उजाला (प्रवाह) : 16 अक्टूबर 2024
7. अमर उजाला : 17 अक्टूबर 2024
8. दैनिक जागरण : 18 अक्टूबर 2024
9. अमर उजाला (संपादकीय) : 19 अक्टूबर 2024
10. अमर उजाला : 20 अक्टूबर 2024
11. दैनिक जागरण : 22 अक्टूबर 2024

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की पत्रकारिता : सामाजिक न्याय और सुधार की आवाज

– **डॉ. मिली सिंह,** असिस्टेंट प्रोफेसर
– **डॉ रेखा सिंह,** सहायक प्रोफेसर

सार—डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, एक प्रमुख पत्रकार भी थे और सामाजिक न्याय, समानता और हाशिए पर स्थित समुदायों के अधिकारों के लिए एक मजबूत वकील थे। उनकी पत्रकारिता सामाजिक अन्याय का सामना करने, जातिगत भेदभाव को चुनौती देने और सुधार की वकालत करने के लिए चिह्नित की जाती है । यह लेख पत्रकारिता में डॉ. बी. आर. अंबेडकर के योगदान की पड़ताल करता है, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि उन्होंने सामाजिक सुधार के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने, जाति व्यवस्था को चुनौती देने और दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रेस का उपयोग कैसे किया। उनके लेखन के विश्लेषण के माध्यम से, यह पत्र दर्शाता है कि अंबेडकर का पत्रकारिता कार्य उनकी सक्रियता का अभिन्न अंग था, जो भारतीय समाज को नया रूप देने के उनके व्यापक प्रयासों में प्रेस की परिवर्तनकारी भूमिका को उजागर करता है।

मुख्य शब्द – बी. आर. अंबेडकर, पत्रकारिता, जाति व्यवस्था, सामाजिक सुधार।

परिचय

डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने पत्रकारिता को सामाजिक न्याय और सुधार की वकालत के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। अंबेडकर के मिशन में पत्रकारिता का महत्व और भारतीय समाज पर इसका प्रभाव स्पष्ट था। उन्होंने शोषितों की चिंताओं को आवाज देने और जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए कई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की स्थापना और संपादन किया।

अम्बेडकर की पत्रकारिता के संदर्भ

1. औपनिवेशिक भारत और सामाजिक पदानुक्रम—19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में, भारतीय समाज जाति के आधार पर गहराई से विभाजित था। दलितों को प्रणालीगत भेदभाव, शिक्षा से बहिष्कार, आर्थिक अभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। साथ ही, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन उत्पीड़न का स्रोत और अवसर दोनों था – इसने भारतीय स्वशासन को दबा दिया, लेकिन अधिकारों और कानूनी समानता के विचारों को भी पेश किया, जिससे अंबेडकर जैसे सुधारक जुड़ सकते थे ।

2. सुधार आंदोलनों का उदय

आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे कई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जाति के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अक्सर पितृसत्तात्मक या सीमित दृष्टिकोण से। दलित वर्ग के एक सदस्य और उच्च शिक्षित नेता के रूप में अंबेडकर ने हाशिए पर पड़े लोगों के अनुभव के भीतर से जातिगत अन्याय को संबोधित करने का प्रयास किया।

3. स्वतंत्र आवाज की आवश्यकता

अंबेडकर ने महसूस किया कि मुख्यधारा के समाचार पत्र या तो दलित मुद्दों को अनदेखा करते हैं या उन्हें उच्च जातियों के नजरिए से प्रस्तुत करते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए, उन्होंने पत्रकारिता की ओर रुख किया ताकि बेजुबानों के लिए एक मंच बनाया जा सके और आम जनता और औपनिवेशिक प्रशासन दोनों से सीधे जुड़ सकें।

अंबेडकर की प्रमुख पत्रिकाएँ और उनका प्रभाव

मूकनायक – 20वीं सदी की शुरुआत में, भारतीय समाज जाति व्यवस्था में मजबूती से जड़ जमाए हुए था, जिसमें दलितों को व्यवस्थागत बहिष्कार, अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ रहा था। हालाँकि भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, और स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था, लेकिन मुख्यधारा के राजनीतिक दलों और प्रेस द्वारा हाशिए पर पड़े समुदायों की चिंताओं को काफी हद तक अनदेखा किया गया। दलितों की अनकही कहानियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक स्वतंत्र मंच की आवश्यकता को पहचानते हुए, अंबेडकर ने उत्पीड़ितों को जगाने और उन्हें सशक्त बनाने के साधन के रूप में मूकनायक – जिसका अर्थ है 'बेजुबानों का नेता' – की शुरुआत की। इस पत्रिका के माध्यम से अंबेडकर ने अपनी सार्वजनिक भूमिका की नींव रखी। मूकनायक पहली बार 31 जनवरी 1920 को महाराष्ट्र की स्थानीय भाषा मराठी में प्रकाशित हुआ था, जिससे यह दलित जनता के लिए सुलभ हो गया। अखबार को कोल्हापुर के शाहू महाराज द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी, जो एक प्रगतिशील शासक और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अंबेडकर के मिशन के महत्व को पहचाना। हालाँकि अंबेडकर अखबार के पीछे मार्गदर्शक शक्ति और बौद्धिक नेता थे, लेकिन उस समय सरकारी कर्मचारी के रूप में अंबेडकर की कानूनी सीमाओं के कारण इसके आधिकारिक संपादक नंदराम भटकर थे। फिर भी, अंबेडकर ने कई संपादकीय और लेख लिखे जो उनकी विचारधारा और दृष्टि को दर्शाते थे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया, उनसे सीखने और आलोचनात्मक सोच को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। अखबार ने जातिगत भेदभाव को कायम रखने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की खुलकर आलोचना की । इसने दलितों को उनके राजनीतिक अधिकारों को समझने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अंबेडकर ने मजदूरों, किसानों और महिलाओं सहित सभी हाशिए के समूहों के बीच एकजुटता पर जोर दिया। हालाँकि मूकनायक का जीवनकाल छोटा था – 1923 में इसका प्रकाशन बंद हो गया – लेकिन इसने भारतीय समाज और अंबेडकर की बाद की सक्रियता पर एक स्थायी प्रभाव डाला। यह दलित संघर्ष की पहली मुद्रित आवाज बन गई और इसने बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे भविष्य के प्रकाशनों को प्रेरित किया। मूकनायक ने निम्नलिखित में एक आधारभूत भूमिका निभाई ।

बहिष्कृत भारत–बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आधिकारिक प्रकाशन था, जो बहिष्कृत समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर द्वारा स्थापित एक संगठन था। अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक सुधार के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता शोषित वर्गों के लिए निरर्थक होगी। मूकनायक के माध्यम से पत्रकारिता के साथ पहले से ही प्रयोग कर चुके आंबेडकर ने व्यापक दर्शकों तक पहुँचने और एक ऐसा मंच बनाने के लिए अप्रैल 1927 में बहिष्कृत भारत की शुरुआत की, जो सूचना, शिक्षा और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से दलितों को सशक्त बनाएगा। यद्यपि वित्तीय बाधाओं और सामाजिक बाधाओं के कारण बहिष्कृत भारत का व्यापक प्रसार नहीं हुआ, फिर भी इसका प्रभाव महत्वपूर्ण था। इसने दलितों में गहरी राजनीतिक चेतना पैदा की और सुधारकों, कार्यकर्ताओं और छात्रों के बीच संवाद के लिए एक मंच तैयार किया। मंदिर प्रवेश आंदोलन और पृथक निर्वाचिका की मांग सहित अंबेडकर के नेतृत्व में आगे के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया।

जनता (लोग) – 1930

जनता की शुरुआत डॉ. अंबेडकर ने 24 नवंबर 1930 को की थी । जनता नाम, जिसका अर्थ है 'लोग', अंबेडकर के लोकतांत्रिक और समतावादी समाज के दृष्टिकोण का प्रतीक था, जहाँ उत्पीड़ित जनता को अपनी आवाज मिलेगी। डॉ. अंबेडकर ने इसका इस्तेमाल दलितों द्वारा सामना किए जाने वाले

सामाजिक अन्याय को उजागर करने, जाति व्यवस्था की आलोचना करने और भारतीय समाज और राजनीति पर हावी ब्राह्मणवादी आख्यानों का मुकाबला करने के लिए किया। यह केवल सूचना का माध्यम नहीं था बल्कि सामाजिक क्रांति का हथियार था।

निष्कर्ष – डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र केवल एक समाचार पत्र नहीं था – यह आवाज, पहचान और प्रतिरोध का एक साहसिक दावा था । एक ऐसे युग में जब हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजों को दबाया या अनदेखा किया जाता था, समाचार पत्र आशा और परिवर्तन की किरण के रूप में उभरा। यह दर्शाता है कि कैसे मीडिया, जब न्याय और समानता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन सकता है। डॉ. अंबेडकर की अग्रणी पत्रकारिता आज भी भारत में सामाजिक न्याय और सार्वजनिक क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती है।

– डॉ. मिली सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
एस.आर.एम.यू. लखनऊ
फेलो आईआईएएस शिमला

– डॉ रेखा सिंह
सहायक प्रोफेसर
आर्यकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन लखनऊ

संदर्भ :

1. कीर, धनंजय डॉ. अम्बेडकर : लाइफ एंड मिशन। मुंबई : पॉपुलर प्रकाशन, 1954 (संशोधित 1990)
2. मून, वसंत (सं.). डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर : राइटिंग्स एंड स्पीचेस, खंड। 17, भाग मुंबई : महाराष्ट्र सरकार, 2003
3. ओमवेट, गेल. अम्बेडकर : टुवर्ड्स एन एनलाइटेनड इंडिया. नई दिल्ली : पेंगुइन बुक्स, 2004.

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की स्थिति (विशेष अध्ययन : परिशिष्ट/गिरिराज किशोर)

ज्योति कुमारी
शोधार्थी (हिन्दी विभाग)

डॉ. रवि रंजन कुमार
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)

शोध सार–ज्ञानार्जन के लिए बाबा साहेब ने जो संघर्ष किया था, उसमें कमी तो आई परंतु समाप्त नहीं हुआ। उच्च शिक्षण संस्थान भी जातीय संस्कार से ग्रसित लोगों से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ। विद्या अथवा ज्ञानार्जन से वंचित किए गए समाज को छुआछूत से मुक्ति मिली तो आरक्षण के प्रति असहिष्णुता के कारण बुलिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आरोपित किया गया नीच सांस्कृतिक चेतना न केवल पीड़ा देती अपितु विचलित भी करती है।

बीज शब्द–जाति, वर्ग,वंचित,चेतना, आरक्षण, पूर्वाग्रह, संघर्ष।

विद्या अथवा ज्ञानार्जन से वंचित किए जाने वाले पात्रों का संघर्ष पौराणिक कथा ही नहीं भारतीय समाज की भी वास्तविकता रही है। इसलिए समाज के एक बड़े वर्ग के लिए शिक्षा दुर्लभ रही। उनकी उन्नत शिक्षा के लिए आरक्षण एक आवश्यक व्यवस्था है। इस व्यवस्था से एक वर्ग के लोगों को सहूलियत हुई। परंतु दूसरे वर्ग के लोगों को अपने हाथ से कुछ बिखरता हुआ महसूस हुआ। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी के हाथ से कुछ निकलता है और उस पर स्वयं का हित हावी हो जाता है तो तर्क और सही–गलत की पहचान अथवा दूसरे के कष्ट का भान नहीं हो पाता। अनारक्षित वर्ग के कुछ लोग इसी मनोदशा से ग्रस्त हो गए। जब भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान में आरक्षण के आधार पर नामांकन प्रारंभ हुआ तो दलित–वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को एक अवसर मिला कि वे भी इंजिनियर बनने का सपना पूरा कर सकें। परंतु इस संस्थान के लोग उनका स्वागत के लिए तैयार नहीं थे। परिशिष्ट उपन्यास का मुख्य पात्र उसी वर्ग का विद्यार्थी है, जिस वर्ग को सदियों तक

शिक्षा से दूर रखा गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में नामांकन के लिए आरक्षण मिलने के बाद पहला बैच होने के कारण उन्हें (आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को) प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ा। जिसके कारण उन पर अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा टोंट किया जाता है–"ओ.वी.वी.आई.पी. यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति।"[1] ऐसे विद्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम से भी अधिक कठिन होता है संस्थान का वातावरण जो उन्हें सहज महसूस नहीं होने देता। अधिकांश बैचमैट, सिनियर और प्राध्यापक उन्हें अपनी आँखों की किरकिरी समझते हैं। दूसरे वर्ग के विद्यार्थी उन लोगों से कम ही बात करते हैं और जब बात भी करते हैं तो कहते हैं–"आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल कोर्स है। कोर कोर्स तो हम लोगों तक की जान निकाल देता है। आप लोगों को इस परेशानी में डालकर सरकार ने ठीक नहीं किया।"[2] जब हम **शेखर : एक जीवनी** पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि पचास के दशक में उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छूआछूत की समस्या थी। परिशिष्ट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अस्सी का दशक आते–आते विश्वविद्यालय में छूआछूत की समस्या समाप्त हो गई थी। अनुकुल अपने घर चिट्ठी में लिखता है– "वैसे यहाँ की छुआछूत वैसी नहीं, जैसी चौधरी साहब के यहाँ देखने को मिली थी न कोई बाथरूम धोने को कहता है न बाहर सोने के लिए।"[3] परंतु दलित वंचित वर्गों की समस्याएँ और संघर्ष समाप्त नहीं हुई। पहले अस्पृश्यता के कारण उन्हें निम्न समझा जाता था उसकी जगह आरक्षित वर्ग का होने पर निम्न समझा जाने लगा। अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलने के बाद भी यह समस्या सुलझ नहीं सकी, अपितु वर्ग निर्धारण की कसौटी जैसे विषयों में उलझ गई।

"आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी समाज दो वर्गों में बँटा है। एक वर्ग की धारणा है कि आरक्षण के कारण अयोग्य लोगों को लाभ मिल रहा है। दूसरे वर्ग का तर्क है कि हजारों सालों तक हमारा शोषण किया गयाय अब जब पहली बार हमें अवसर मिला है तो ये अवसर भी छीनने का प्रयास किया जाता है।"[4] जिस वर्ग ने हजारों वर्षों तक अपने जैसे दूसरे लोगों को निम्न और स्वयं को श्रेष्ठ समझा उनके बच्चे भी कंफर्मेशन बायस्ड हो गए कि हम कुछ विशेष हैं, इसलिए उत्तम संसाधन पर हमारा अधिकार होना चाहिए। गिरिराज किशोर ने खन्ना को इसी तरह के विचार से प्रेरित पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। वह अनुकूल से कहता है–"अगर तुम अपनी सीमाओं को समझते हो तो ठीक है...नहीं समझते तो समझो। रियाया की स्थिति से उपर उठने में अभी समय लगेगा। अगर हम लोगों की बराबरी करनी थी तो वैसा ही बीज चाहिए था।"[5] कभी कहता है– "आएंगे चोर दरवाजे से और चाहेंगे कि बन जाएँ सी.वी. रमण।"[6]

सामान्यतः हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ ढलने में कठिनाई होती है। आई. आई. टी. में पठन–पाठन अंग्रेजी में होता है। लोग आपस में भी फर्राटेदार अंग्रेजीमें बात करते हैं। इतना ही नहीं हिन्दी को कमतर समझा जाता है–"यह कोई लैंगवेज है? इसमें केवल गालियाँ दी जा सकती है और सब्जी खरीदी जा सकती है। हमलोगों को इस हिन्दी प्रोटोगोनिस्ट के खिलाफ जिहाद छेड़ना चाहिए।"[7] इस तरह के माहौल से खिसियाकर दलित छात्रनेता रामउजागर कहता है–"यदि इन भंगी, चमारों, धोबियों, गोंडों वगैरह को बाभनों, ठाकुरों और बनियों के बच्चों से अपने बच्चों की बराबरी करनी है तो सबकुछ बेच–बाचकर अपने बच्चों को कान्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। तभी जबान मरोड़ अंग्रेजी बोलकर उनके बच्चों को पछाड़ेंगे।"[8]

गिरिराज किशोर ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दलित छात्र की आत्महत्या के विषय को पुरजोर तरीके से उठाया। उपन्यास का दो पात्र मोहन और राम उजागर आत्महत्या कर लेता है। कई दशकों के बाद भी इस विषय की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। क्योंकि आईआईटी में अभी भी आत्महत्याएं हो रही है। 15 फरवरी 2023 को आईआईटी बॉम्बे का दलित वर्ग का छात्र दर्शन सोलंकी ने आत्महत्या कर लिया। उनके परिवार ने बताया कि "एक महीने पहले जब वह घर

आया था तो कह रहा था कि छात्रों को यह पसंद नहीं है कि मैं मुफ्त में पढ़ रहा हूं लोग जलते हैं पूछते हैं तुम मुफ्त में क्यों पढ़ रहे हो जबकि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं।''[9] 8 जुलाई 2023 को आईआईटी दिल्ली का दलित छात्र आयुष आशना ने आत्महत्या कर लिया। आईआईटी दिल्ली के छात्रावास में सितंबर 2023 में दलित छात्र अनिल कुमार का शव मिला। इन छात्रों के परिजनों का आरोप था कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़ित किये जाने के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। इन मामलों में पुलिस ने शिकायत भी दर्ज नहीं किया था मार्च 2025 में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद प्राथमिकी दर्ज किया गया।

इस तरह की घटनाओं के बाद रिपोर्ट बना दिया जाता है कि कठिन पाठ्यक्रम और बेहतर प्रदर्शन ना कर पाने के कारण हतोत्साहित होकर छात्र ने जान दे दी परंतु गिरिराज किशोर आईआईटी में कार्य करने और परिसर की परिस्थितियों का बेहतर अनुभव रखने वाले लेखक थे। उन्होंने इस संस्थान में होने वाले सूक्ष्म भेदभाव को देखा और जिया था इसलिए परिशिष्ट के विद्यार्थी चिख–चिखकर कहते हैं की आत्महत्या पढ़ाई अथवा प्रदर्शन के कारण नहीं भेदभाव के कारण हुआ है।

निष्कर्ष–उच्च शिक्षण संस्थान में विविधता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि वंचित वर्गों के विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ी। परंतु आरक्षित वर्ग का होने के कारण उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। आवश्यकता है कि आरक्षण को भिक्षा अथवा खैरात के रूप में न देखकर सामाजिक सुधार की पद्धति की दृष्टि से देखा जाए। जिन वर्गों (दलित, पिछड़े, महिला...) के उत्थान का मार्ग लम्बे समय तक अवरुद्ध रखा गया, उन्हें थोड़ी सी विशेष सुविधा मिलने पर सहिष्णु हुआ जाए। न कि उनके प्रति

ज्योति कुमारी
शोधार्थी (हिन्दी विभाग)

डॉ. रवि रंजन कुमार
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)

केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, राँची

संदर्भ :

1. किशोर, गिरिराज, परिशिष्ट, पृष्ठ115, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, दूसरा संस्करण 2011
2. वही, पृष्ठ115
3. वही, पृष्ठ115
4. डॉ. विकास दिव्यकीर्ति, युट्युब चैनल, दृष्टि आई.ए.एस
5. किशोर, गिरिराज, परिशिष्ट, पृष्ठ174, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, दूसरा संस्करण 2011
6. वही,पृष्ठ209
7. वही,पृष्ठ136
8. वही,पृष्ठ129
9. NDTV India News, 15 February 2023, NDTV. Com

Dr. Babasaheb Ambedkar and Linguistic Equality in India

- Dr. Kishorkumar G. Gaikawad
Asst. Professor

Abstract :

This paper is an attempt to throw light on Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution for linguistic equality in India. Linguistic equality is an important concept that refers to the idea that all individuals should have equal access to and opportunities for using language. This includes the right to use one's own language and to have access to education and other resources in one's own language. As an architect of the Indian Constitution, Ambedkar advocated for the recognition and protection of linguistic diversity, ensuring that multiple languages were given official

status. He emphasized the importance of mother tongue education and pushed for policies that would enable marginalized communities to access education and government services in their native languages. Ambedkar's efforts extended beyond mere recognition of languages; he sought to create a framework that would promote linguistic equality in practice, addressing the power imbalances that often exist between dominant and minority languages. His vision of linguistic equality was intrinsically linked to his broader mission of social emancipation, as he understood that language rights were essential for the full participation of all citizens in India's democratic process.

Key Words : Linguistic Rights, Social Justice, Minority Languages, and National Integration etc.

Introduction :

Dr. Babasaheb Ambedkar was a visionary leader who fought for the rights of the marginalized and disadvantaged sections of Indian society. One of his key contributions was his advocacy for linguistic equality, which recognized the importance of language in the development of a just and equitable society. Ambedkar believed that language was an essential tool for communication, education, and social mobility, and he worked tirelessly to promote the use of regional languages in education and government. He recognized that language was a fundamental aspect of cultural identity and that the imposition of a single language or culture on a diverse population could lead to social unrest and inequality. Through his efforts, Ambedkar helped to create a more inclusive and diverse society in India, where people from different linguistic and cultural backgrounds could thrive and contribute to the nation's development.

Dr. Babasaheb Ambedkar advocated for linguistic diversity while emphasizing the need for a common language to facilitate communication across the nation. He proposed a balanced approach that respected regional languages while promoting Hindi and English as link languages. Ambedkar's efforts led to the inclusion of provisions in the Constitution that safeguarded linguistic rights and prevented discrimination based on language. He championed the cause of marginalized communities by advocating for their languages and dialects to be recognized and preserved. Ambedkar's vision of linguistic equality extended beyond mere recognition; he

saw language as a tool for social empowerment and educational advancement. His contributions continue to influence India's language policies and serve as a foundation for promoting linguistic harmony in a diverse nation.

Understanding that language is essential for social and political empowerment, Dr. Ambedkar played a vital role in promoting linguistic equality in India. He believed that ensuring equal rights and recognition for different languages would help marginalized communities gain a voice and participate more fully in society. His advocacy for linguistic diversity laid the groundwork for policies that aimed to protect minority languages while fostering a sense of national unity. Dr. Ambedkar advocated for the creation of linguistic states, which means organizing Indian states according to the languages spoken by their populations. He believed that this approach would improve governance by allowing local governments to better understand and address the needs of their communities, while also helping to preserve the unique cultures and languages of different groups. By promoting linguistic states, Ambedkar aimed to create a more inclusive and representative political structure in India that respected its diverse linguistic heritage.

In his vision for a unified India, Ambedkar advocated for a balanced approach to language policy. He understood the delicate balance required to acknowledge and preserve India's rich linguistic diversity while simultaneously promoting a sense of national cohesion. This nuanced stance reflected his awareness of the potential for language to both unite and divide a nation as diverse as India. Ambedkar supported the idea of linguistic states, recognizing that linguistic identity was a significant factor in regional cultural expression and political organization. However, he was acutely aware of the dangers of extreme linguistic chauvinism. He cautioned against allowing regional linguistic pride to overshadow the broader national interest, fearing that it could lead to fragmentation and hinder the process of nation-building. In his search for a solution to India's linguistic conundrum, Ambedkar proposed an innovative and somewhat controversial idea. He suggested Sanskrit as a potential national language, believing it could serve as a neutral choice that wouldn't favor any particular region or linguistic group. This proposal stemmed from his belief that Sanskrit, as the classical language of India, held a unique position in the

country's cultural heritage and could potentially bridge the linguistic divides among different regions. Ambedkar's concern for linguistic equality extended beyond the question of a national language. He was a staunch champion of the rights of minority language speakers, recognizing that linguistic minorities often faced discrimination and marginalization. He stressed the importance of mother tongue education, understanding that learning in one's native language was crucial for cognitive development and cultural preservation.

The impact of Ambedkar's views on linguistic equality is evident in the constitutional provisions he helped craft. The Indian Constitution, under his guidance, recognized multiple official languages, reflecting the country's linguistic diversity. It also included safeguards to protect linguistic minorities, ensuring their right to preserve and promote their languages and cultures. Furthermore, Ambedkar's influence can be seen in the Three Language Formula adopted in India's education policy. This formula aims to promote multilingualism and ensure that students learn their regional language, Hindi (or another modern Indian language in Hindi-speaking areas), and English. This approach reflects Ambedkar's vision of a linguistically diverse yet unified India. Ambedkar's contributions to linguistic equality went beyond mere policy formulations. He understood that language was intrinsically linked to social justice and equality. By advocating for linguistic rights, he was also fighting against the social hierarchies and inequalities that were often reinforced through language policies.

Conclusion :

Dr. Babasaheb Ambedkar's views on linguistic equality were characterized by a remarkable balance between unity and diversity. His advocacy for a common national language was tempered by his respect for India's linguistic plurality. By championing the rights of linguistic minorities and emphasizing the importance of mother tongue education, Ambedkar laid the foundation for a more inclusive and diverse linguistic framework for India. His legacy continues to influence India's language policies and debates, serving as a reminder of the ongoing challenge of maintaining linguistic diversity while fostering national unity.

- Dr. Kishorkumar G. Gaikawad
Asst. Professor,
Dept. of English Dadapatil Rajale Arts and Science College, Adinathnagar.
Tal: Pathardi, Dist : Ahmednagar. Maharashtra.
Mobile No.- 9850387711

Works Cited :

- Ambedkar, B.R. States and Minorities. Thacker & Co., 1947.
- Ambedkar, B.R. Thoughts on Linguistic States. Aligarh, 1989.
- Jadhav, A. "B.R. Ambedkar and the Making of India's Linguistic Policy." Language in India, vol. 19, no. 1, 2019.
- Mehendale, Archana. "Ambedkar and Language: The Phonetics and Linguistics of Power." Economic and Political Weekly, vol. 26, no. 52, 1991.
- Sen, Suvarna. "Babasaheb Ambedkar and the Discourse on Language Policy." Economic and Political Weekly, vol. 43, no. 23, 2008.

"Caste and Identity Politics : Challenges and Opportunities for Social Justice in the Preview of the Supreme Court of India as Good Governance"

First Author:* **Mr. Parminder**
Second Author: ** **Dr. Manjit Singh**

Abstract

This article probes the role of positive discrimination in the emerging discourse and practice of good governance in the developmental liberalization of the Indian economy, through a critical examination of its interface with the liberalization of politics. The term "affirmative action" is known in the United States, and reservations in India, as referring to specific measures such as quotas which are designed to redress the effects of past discrimination against a particular group.

1. INTRODUCTION

The demographic category of caste holds significance to the people of India in contrast to other minorities and disadvantaged groups. Its continuing influence in Indian politics makes it a salient issue for governance as well as for the consolidation of a modern democratic state. This hierarchical social order is in turn buttressed by an ideology of purity and pollution, which is closely linked to the concept of caste. Scheduled castes (SCs) and scheduled tribes (STs) who are designated as being at the bottom of this social hierarchy, have historically been subject to various disabilities arising from the traditional notion of caste.

1. HISTORICAL BACKGROUND

The caste system in India is an important dimension of inequality in the country. Beginning around 1000 BC, the caste system has been a means of creating and maintaining a social hierarchy in the Indian subcontinent. The caste system divides Hindus into four main categories - Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and the Shudras. The Bhagavad Gita labels these people based on their inherent

abilities and attributes and assigns them to specific forms of work. The Dalits rank below all four groups and were considered to have no varna; they were regarded as 'achoot' or 'untouchables'. The Shudras and the Dalits were segregated from the rest of the people by being denied

2. CHALLENGES IN CASTE AND IDENTITY POLITICS

Hindu society has been plagued by the varna and jaati system for centuries, a system that never had so deep a hold over the subjugated as when they were theoretically free. Though caste-based discrimination was constitutionally abolished by the Indian government in 1950, its ramifications and visages still linger today. Affirmative action policies were implemented to provide historically disadvantaged groups with a better opportunity, oftentimes requiring higher caste employment and educational quotas.

India is a country of unity in diversity with wide ranges of cultures and traditions. Deep-rooted system of caste-based hierarchy has caused the lower caste people to suffer from various social and political injustices and finally, casteism has made a permanent seat in village or local level politics or even at the national level.

3. ROLE OF THE SUPREME COURT IN GOOD GOVERNANCE

Judicial activism is a widely recognized and influential concept in which the judiciary, by actively engaging in various actions and interventions, meticulously shapes and profoundly influences the functioning of the government. Through its firm determination and unyielding dedication, the judiciary not only safeguards and preserves the system but also actively participates in the continuous enhancement and betterment of society at large. Furthermore, the noble responsibility bestowed upon the judiciary encompasses serving the wider community, especially those individuals who find themselves burdened with economic disadvantages and hardships. In its fundamental role as a powerful guardian and arbiter of justice, the judiciary ensures that any systemic changes.

4. JUDICIAL ACTIVISM FOR SOCIAL JUSTICE

During the early years of its inception, the Indian Supreme Court gave several landmark decisions highlighting the significance of social justice in a democracy, using various constitutional provisions for interpretation to enable the state to take action to

achieve the goals of equality and justice. The Kesavananda Bharathi v State of Kerala (1973) was a classic example of the said proposition, where the court held that the state is required to take positive steps to ensure social and economic justice, though refrained from interfering with the power of Parliament to amend the Constitution. Subsequently, in Indra Sawhney v Union of India (popularly called the Mandal case), the court upheld the centre's decision to provide 27% reservation for OBCs, but directed that the creamy layer among them should be excluded from this list, said reservation not be extended to super specialty courses, and the total quantum of reservations should not exceed 50%. The court also reiterated that reservation should only be a temporary measure to bring the backward classes to the forefront of society and it should not be used indefinitely.

5.ENSURING ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN GOVERNANCE

In the Vineet Narain v. Union of India case, the Supreme Court had issued directions for the setting up of a high-powered committee called the 'LokPal' to inquire into allegations of corruption against public functionaries, political and bureaucratic, and to prosecute these functionaries where necessary. Unfortunately, the government has not yet implemented this order. It is necessary for the judiciary to ensure that the executive complies with the rule of law by fastening various schemes and programs with specific deadlines, monitoring and fixing accountability of the officials, and ensuring that the responsibilities are fixed for the transgressions of law.

CONCLUSION

Our analysis here has been located within a general framework that relates social justice and governance through the concept of citizenship. This framework has evolved in the context of a particular view of the modern state. This modernist view portrays the state as an institution above society and national citizenship as the primary form of mass political identity within a 'bounded' territory. We have argued that this model provides a useful normative context for exploring the dilemmas of identity politics for social justice. We have suggested that it is possible to distinguish between 'degenerate' forms of identity politics which undermine the prospects for social justice and 'progressive' forms which extend these prospects.

- Dr. Manjit Singh
Assistant Professor
of Law at Dept. of Law
Guru Nanak Dev
University, Amritsar

- Mr. Parminder
Research Scholar
of Law at Dept. of Law
Guru Nanak Dev
University, Amritsar
Mob. 98764 00869

References :

Harikrishnan, S. (2022). Making space : towards a spatial history of modernity in caste- societies. Social History.

Chrispal, S., Bapuji, H., & Zietsma, C. (2021). Caste and organization studies: Our silence makes us complicit. Organization Studies.

Ahmed, A. (2023). Social mobility and politicisation of caste among the Rayeens of Uttar Pradesh. Contemporary South Asia.

Upadhya, C. (2023). Caste and capital. The Oxford Handbook of Caste.

Nair, R. B. (2020). Caste and language. Handbook of pragmatics.

Thirumali, I. (2021). India: Nation and its People: Castes and Parties in the Making of Democracy.

Suresh, B. G. S. (). In Search of Political Culture: Location of Education in Indian Democracy. Culture Change in India.[

Kumar, S. (2023). Deconstructing Caste-Based Private Discrimination: Comparative Examination of India and Canada.

Dey, S. K. (2023). Identity and Tipping Point in Political Choice. Available at SSRN 4668932.

Rai, D. (2022). Contested Representation: Dalits, Popular Hindi Cinema, and Public Sphere.

Bhat, A. (2024). Caste politics in India with special reference to Uttar Pradesh. Authorea Preprints.

Gudavarthy, A. & Vijay, G. (2020). Social policy and political mobilization in India: Producing hierarchical fraternity and polarized differences. Development and change. Baruah, S. K. A. (2022). Revolutionaries-Thought and Works. Indian and World Social Reformers and Revolutionaries, 11.

A literature review on the Impact of Surya Namaskar on Athlete's Health : Physical, Physiological and Psychological perspectives"

- Dr. Himani Malhotra

Abstract : Surya Namaskar is an ancient yoga practice consists of a series of 12 postures performed in sequence, combining movement, breath control, mindfulness. It is becoming popular for its health advantages, particularly in relation to sports and fitness. The aim of the present study is to inquire that how Surya Namaskar impacts athletes' physical, physiological and psychological health. The improvement areas covered in this review include flexibility, muscle strength, cardiovascular fitness, respiratory function, mental health and exercise recovery. The findings demonstrate considerable positive effects in all of these aspects, which means Surya Namaskar is a good and useful complementary exercise among athletes in the context of enhancing sports performance, accelerating recovery and avoiding injuries. This literature review illuminates the potential of Surya Namaskar in enhancing holistic health of athletes and proves that the practice is an

effective supplement of sports training programs and recovery programs.

Keywords : Surya Namaskar, Physical, Physiological, and Psychological Health

Introduction : Surya Namaskar or Sun Salutation is a classical yoga practice comprising of 12 interrelated poses. It is a combination of mindfulness, breath control and physical movement and hence a full body workout for overall wellbeing. It is increasingly gaining popularity based on its health benefits particularly when it comes to sports and fitness. The aim of this literature study is to investigate the impact of Surya Namaskar on athletes, with an emphasis on their physical, physiological, and psychological health.

Objectives :

1. To examine the physical benefits of Surya Namaskar on athlete's health.

2. To study the physiological impacts of Surya Namaskar on athlete.

3. To evaluate the psychological effects of Surya Namaskar on athlete.

4. Evaluation of the effect of Surya namaskar as a sports injury rehabilitation method.

Methodology : Using the databased such as: PubMed, Scopus and Google Scholar, the entire literature review was done. The keywords were used to locate the right studies like: 'Surya namaskar, Sun Salutation, Yoga for athletes, Physiological and psychological benefits of Surya namaskar' and also limited the search of articles specifically which are published in English in the last 20 years. General yoga practices were eliminated from the inclusion criteria, which were only applied to researches focusing the impact of Surya Namaskar on athlete's health. Observational research and randomized controlled trials were also included. After excluding study reports lacking abstracts, 95 papers were found, following the screening titles and abstracts for relevance to Surya namaskar, 45 articles were found for further review. The selected studies were categorized into physical, physiological, psychological health benefits where important findings were summarized and a few common themes brought out.

Results :

1) Physical Health Benefits of Surya Namaskar :

Surya Namaskar is well known for enhancing the flexibility and it is significant aspect of sports performance and injury prevention. The series of poses stretch the hamstring, shoulders,

hips and spine among others muscle groups. Bhutkar et al. showed that, in 12 weeks of practicing Surya Namaskar, the flexibility increased significantly in college athletes in the hip and lumbar areas (Bhutkar et al., 2008). These flexibility improvements assist an athlete to excel in sports where a broad spectrum of movement is needed as is the case with Gymnastics and Martial arts.

Surya Namaskar's different poses engage multiple muscle groups which promote muscle strength and endurance. For example- the arms, back, and core are engaged in Bhujangasana (cobra pose). According to study, after 8 weeks of practicing Surya Namaskar, muscle strength and endurance improved in Surya Namaskar practitioners in a much greater manner compared to athletes who followed conventional stretching exercises. This is beneficial in Cycling and Rowing because of such improvements in muscle performance. Several poses in Surya Namaskar also enhances balance and coordination. A study by Cowen and Adams (2005) had established that practicing Surya Namaskar regularly, helped in balance of athletes and which increased their neuromuscular coordination (Cowen and Adams, 2005). Hence, in the case of players competing in sports such as Basketball, Tennis and Soccer, improved balance is crucial.

2) Physiological Effect of Surya Namaskar :

Surya Namaskar also offers aerobic benefits, when performed dynamically because it increases the heart rate and also it has a beneficial effect on cardio-vascular health by positively improving the heart rate variability. It was found out that; cardiorespiratory endurance of young athletes had increased substantially after 6 weeks of daily exercise. This enhancement assisted the athletes to be better in endurance sport such as Swimming and Running.

The workout is also useful to keep the metabolism in check by activating endocrine glands: thyroid and the adrenal glands. Harinath et al. (2004) suggest that Surya Namaskar performed daily enhanced hormonal balance that is critical to recovery and performance particularly in Bodybuilding and Weightlifting where metabolic efficiency is necessary (Harinath et al., 2004).

Surya Namaskar breathing patterns and postures enhance the lung capacity and efficiency of the breath, which is useful in the athletes who engaged in oxygen-demanding activities: Swim-

ming and Long-distance running. Researchers found out that athletes that included Surya Namaskar in their training compared to non-practitioners, had improved respiratory endurance and greater vital capacity.

3) Psychological Impacts of Surya Namaskar :

Training and competition are the cause of many psychological stresses among athletes. Through the activation of para-sympathetic nervous system, Surya Namaskar minimises the stress level by combining the mindfulness & breathing exercises. As per few studies, those athletes who performed Surya Namaskar for 8 weeks had minimum anxiety and stress level, that is important in maintaining mental focus during Archery and Shooting games.

Surya Namaskar practice improves cognitive functions : such as : memory, concentration, and decision making. Nivethitha et al. indicate that the participants who were practising Surya Namaskar had better cognitive performance (Nivethitha et al., 2016). This is especially beneficial for strategy-based sports like: Chess, Golf etc.

Surya Namaskar releases of mood-enhancing neurotransmitters and endorphins. According to a study that was conducted among collegiate athletes, individuals who performed Surya Namaskar also improved the moods and were more enthusiastic about the practice and competition.

4) Surya Namaskar as Tool for Rehabilitation :

By enhancing the flexibility and balanced muscle development, Surya namaskar minimises the risk of sports injuries in athletes. It is also a recovery rehabilitation tool to recover the athletes. According to the research, athletes who had their musculoskeletal injuries rehabilitated and performed Surya Namaskar bounced back to their mobility sooner in comparison to those who did not.

Conclusion : Surya Namaskar is demonstrated to possess the numerous positive effects in the case of athletes, such as : physical fitness, physiological and psychological wellness. It is a good complimentary exercise towards enhancement of sports performance, acceleration of recovery, and injury prevention. The requirement for long-term research and the variation in the study methodologies, however, emphasize the need of more research to create the uniform standards to integrate

Surya Namaskar in sports training programs. The present literature review demonstrates the potential of Surya Namaskar in promoting the holistic health of athletes and proves its usefulness to be included in sports training and recovery programs.

- Dr. Himani Malhotra
Assistant Professor
Department of Physical Education,
University of Delhi, India,
Mobile: 09868720822

References :

• Bhutkar, P. M., Bhutkar, M. V., Taware, G. B., & Doddamani, B. R. (2008). Effect of Suryanamaskar Practice on Cardio-respiratory Fitness Parameters : A Pilot Study. 1.

• Cowen, V. S., & Adams, T. B. (2005). Physical and perceptual benefits of yoga asana practice: Results of a pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 9(3), 211–219. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2004.08.001

• Harinath, K., Malhotra, A. S., Pal, K., Prasad, R., Kumar, R., Kain, T. C., Rai, L., & Sawhney, R. C. (2004). Effects of Hatha Yoga and Omkar Meditation on Cardiorespiratory Performance, Psychologic Profile, and Melatonin Secretion. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 10(2), 261-268. https://doi.org/10.1089/107555304323062257

• Nivethitha, L., Mooventhan, A., & Manjunath, N. K. (2016). Effects of Various Prānāyāma on Cardiovascular and Autonomic Variables. Ancient Science of Life, 36(2), 72. https://doi.org/10.4103/as1.ASL_178_16

Reconstructing Historical Narratives through Biopics : A Study on the Film Dr. Babasaheb Ambedkar

- Fathima Sullami T.A
Assistant Professor

Abstract

Films are a powerful medium of storytelling that combine visual, auditory, and narrative elements to entertain, inform, and evoke emotions. Since their inception, films have evolved into various genres, including action, drama, comedy, horror and fantasy, among others. One significant genre within cinema is the biographical films or biopics which adapt biographies into films. It focuses on portraying real events, figures, or periods from the past and hold a unique place in the cinematic world, bridging the gap between historical documentation and artistic interpretation. These films offer a medium through which historical narratives can be revisited, reinterpreted, and reconstructed for contemporary audiences and provide them with visual and emotional insights into the lives of significant figures, often shaping public

perception and collective memory. Many biopics contributed in that way and one such impactful biopic is Dr. Babasaheb Ambedkar (2000), which delves into the life and legacy of Dr. B.R. Ambedkar, a pivotal figure in Indian history known for his relentless fight against caste discrimination and his role in drafting the Indian Constitution. Hence this paper explores how the biopic Dr. Babasaheb Ambedkar reconstructs historical narratives, balancing between historical accuracy and artistic interpretation, and how it makes an impact on public perception.

Key words : Biopic, adaptation, recreation, historical accuracy, artistic interpretation.

The delayed recognition of Dr. B.R. Ambedkar in Indian films, and media is a reflection of the deeply entrenched caste biases and political dynamics within Indian society. For decades, mainstream narratives often marginalized or omitted Ambedkar's contributions, focusing instead on other figures of the independence movement. This erasure can be attributed to the discomfort felt by many towards Ambedkar's radical views on caste reform and his critique of Hindu orthodoxy. Educational institutions, influenced by prevailing social and political sentiments, rarely highlighted his pivotal role in drafting the Indian Constitution and his relentless fight for social justice. However, Ambedkar's enduring legacy and the resilience of his ideas could not be suppressed indefinitely. Over time, his significance gained global acknowledgment, driven by the scholarly works of academics, the activism of Dalit movements, and the eventual inclusion of his life and work in various media including films. Indian cinema has gradually embraced the monumental legacy of Dr. B.R. Ambedkar through a series of biographical films and documentaries that shed light on his life and contributions. Notable among these is the biopic Dr Babasaheb Ambedkar (2000) directed by Jabbar Patel, produced by National Film Development Corporation and the Ministry of Social Justice and Empowerment was made in nine languages, including Hindi and English. The movie won the National Film Awards for best feature film in English, and Best Actor for Mammooty's performance as Ambedkar.

Balancing Historical Accuracy and Artistic License. Biopics occupy a unique space in the cinematic world, blending historical facts with artistic

storytelling. They provide audiences with accessible interpretations of historical figures' lives, often highlighting key events and personal struggles. It serves as powerful medium through which historical narratives are constructed and disseminated. Often, they blur the boundary between documentary and fiction, to portray the life and times of real people, focusing on key events and personal struggles. Unlike documentaries, which strive for factual accuracy and objectivity, biopics employ creative storytelling techniques to engage viewers in a touching way. Adaptations can range from faithfully reproducing the original work to taking considerable creative liberties in reinterpreting the content. Regardless of the approach, all adaptations are essentially re-creations or remakes, where the source text is transformed into a target text, or they may serve as a 're-interpretation' of the original. The debate over the primacy of the source text, particularly in terms of faithful reproduction, has been a longstanding issue in adaptation studies. "Retellings of history can never be pure, literal or absolute". (Inglis, popular music history on screen: the pop/rock biopic,2007). This artistic license allows filmmakers to highlight specific aspects of a person's life, making their story accessible and relatable to a broad audience. "Like a history book, a historical film, despite Hollywood's desire for "realism", is not a window onto the past but a construction of a past; like a history book, a film handles evidence from the past within a certain framework of possibilities and tradition of practice. For neither the writer of history nor the director of a film is historical literalism a possibility" (Rosenstone R. 1995).

In Dr. Babasaheb Ambedkar (2000), the filmmakers likely faced the challenge of balancing the demands of historical accuracy with the need to create a compelling narrative for the audience. Yet the biopic meticulously portrays significant events from Ambedkar's life, such as his efforts to eradicate untouchability, his role in the Indian independence movement, and his contribution to drafting the Indian Constitution. These events are depicted with a high degree of fidelity, ensuring that viewers gain an understanding of Ambedkar's monumental contributions to Indian society. As Ambedkar gradually ascends to leadership, the film compellingly depicts his motivations behind the 1927 protest at Mahad, the

burning of the Manusmriti later that year, and the 1930 agitation at the Kalaram temple. However, the film also takes artistic liberties to enhance its narrative appeal. For instance, certain dialogues and scenes are dramatized to emphasize Ambedkar's emotional and intellectual struggles. These creative elements serve to humanize Ambedkar, presenting him not just as a historical icon but as a relatable and inspiring figure. This balance between accuracy and artistic interpretation is crucial for engaging audiences while preserving the essence of historical events.

To fully appreciate the reconstruction of historical narratives in films, it is essential to apply an intersectional lens. Intersectionality; a concept popularized by Kimberlé Crenshaw, examines how various social identities, such as race, gender, and class, intersect to create unique modes of discrimination and privilege. The film touches upon the intersectionality of caste and class, particularly in scenes that highlight Ambedkar's educational journey and his interactions with the British colonial administration. These scenes illustrate the layered nature of oppression and the multifaceted strategies Ambedkar employed to navigate and challenge these structures. Also, there are significant female figures in Ambedkar's life, such as his wife Ramabai Ambedkar, whose character provides insight into the personal sacrifices and emotional support that underpinned Ambedkar's public life. While the primary focus remains on Ambedkar's fight against caste discrimination, the portrayal of women in the film sheds light on the gender norms of the time.

Ramabai's character, for example, is depicted as a resilient and supportive partner, highlighting the often-overlooked contributions of women in historical movements. However, the film could be critiqued for not fully exploring the intersection of caste and gender oppression, an area where further depth could have provided a more nuanced narrative.

Success of a film lies in its effective use of cinematic techniques and narrative structure as it employs powerful visuals, symbolic imagery, and evocative music to create an immersive experience. The use of flashbacks and chronological storytelling helps to contextualize Ambedkar's actions and decisions, thereby providing a coherent narrative flow. The biopic also makes strategic use of dialogues and

monologues to convey Ambedkar's thoughts and philosophies. These narrative devices allow the audience to engage with Ambedkar's intellectual journey, making complex ideas accessible and compelling. Through these techniques, the film not only informs but also inspires viewers to reflect on the ongoing relevance of his ideals.

Biographical Film adaptations often face criticism regarding their fidelity to the source text or the accurate portrayal of the biographical subjects. However, absolute faithfulness is not feasible, as adaptation is not simply replication but rather a creative reimagining. These works should be recognized as new artistic creations. By translating Ambedkar's life story to the big screen, the film has reached a broad audience, many of whom may have previously been unfamiliar with his contributions and has helped to imprint Ambedkar's place in the collective memory of Indian society, fostering a deeper appreciation for his role in shaping modern India. Moreover, the biopic has sparked discussions on social justice and equality, highlighting the enduring relevance of Ambedkar's ideals. It serves as a reminder of the ongoing struggles against caste discrimination and the importance of upholding the principles enshrined in the Indian Constitution. Hence by reconstructing Ambedkar's narrative, the film has contributed to a more nuanced and inclusive understanding of Indian history.

- Fathima Sullami T.A
Assistant Professor of English
MES College Nedumkandam, Idukki
Research Scholar, Department of English
Maharaja's College, Ernakulam,
(Kerala) 685553, Mob.94000 56715

References :

- Dr. Babasaheb Ambedkar. Directed by Jabbar Patel, Govt. of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, 2000.
- Bhagat, Manoj Pralhad. "Analysis of Social Vision of Dr BR Ambedkar in Gail Omvedt's 'Seeking Begumpura'." International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 22-30. ResearchGate, doi:10.48175/ijarsct-8117.
- Inglis,I. popular music history on screen: the pop/rock biopic. Popular Music History, 2007.77-93
- Panday, Ajay Shankar. "Role of Dr. BR Ambedkar in Indian Woman Empowerment." International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, vol. 4, no. 3, 2023, pp. 95-105. ResearchGate, doi:10.48175/ijarsct-8635.
- Rosenstone, Robert A. History on Film/Film on History. Pearson Longman, 2006.

मूल निवासी सभ्यता संघ द्वारा सांची, मध्यप्रदेश में आयोजित तीन दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय महासंगीति का सफल आयोजन सम्पन्न

मुनिटा संवाददाता, सांची, मूल निवासी सभ्यता संघ के द्वारा होटल संबोधि इंटरनेशनल, सांची, विदिशा मध्यप्रदेश में 25–27 अक्टूबर 2025 द्वितीय राष्ट्रीय महासंगीति का आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस आयोजन में भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र मुख्य रूप से शामिल थे।

इस महासंगीति में विभिन्न विधाओं के कार्यक्रम आयोजित किये गये—कलाचारिक, फिल्म प्रदर्शन, नाटक प्रस्तुति और साहित्यिक चर्चाएं प्रमुख आकर्षक रहे।

दिनांक 25 अक्टूबर 2025 शनिवार को महासंगीति का शुभारंभ संविधान गीत के कोरस गान से हुआ, मुख्य उद्घाटक मूल निवासी शैलेश नरवाडे (फिल्म निदेशक जयंती) मुख्य अतिथि एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन (उच्च न्यायालय प्रयागराज) मूल निवासी सीमा बाबूसिंह वास्कले (राष्ट्रीय प्रभारी जयस, बड़वानी), विशिष्ट अतिथि आर.एल. ध्रुव (राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ) मूल निवासी सुनील कुमार (राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी सभ्यता संघ) एडवोकेट के एस. चौहान (वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली), डॉ. दीपा श्रावस्ती (केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य—बामसेफ) प्रोफेसर नीलिमा बागड़े (केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य—बामसेफ), मूल निवासी शर्मिष्ठा गौतम (केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य—बामसेफ), डॉ. पी. कोमल एवं मूल निवासी उमेश पटेल (राज्य कार्यकारिणी सदस्य मध्यप्रदेश, बामसेफ)। उद्घाटन सत्र का मंच संचालन मूल निवासी अरूणा तिरपुडे (राष्ट्रीय महासचिव, मूल निवासी सभ्यता संघ) द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र में साहित्यिक वेबसाइट और वेब पत्रिका—'बेगमपुरा का आह्वान' का बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी आर.एल. ध्रुव के कर कमलों द्वारा लोकार्पण भी किया गया।

इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय संगीति में डॉ. तारा परमार उज्जैन (म.प्र.), सम्पादक—'आश्वस्त' को उनके अमूल्य साहित्यिक व सामाजिक कार्यों से भारत की मूल सभ्यता को जीवंत बनाए रखने में अतुलनीय योगदान देने के लिये 'मूल निवासी सभ्यता संघ' **''भारतीय वाङ्मय सम्मान 2025''** संथाली शाल, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान—पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार डॉ. कुसुम वियोगी दिल्ली को **''भारतीय कथा वाङ्मय सम्मान 2025''** से संथाली, शाल, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण—पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस त्रि—दिवसीय आयोजन में हजारों मूल निवासी सुदूर राज्यों से पधारें। जिसमें डॉ. ईश कुमार गंगानिया, डॉ. पुष्पा सिंह एवं श्रीमती गंगानिया आदि प्रमुख हैं।

समापन सत्र में मूल निवासी सुनील कुमार (राष्ट्रीय अध्यक्ष—मूल निवासी सभ्यता संघ) द्वारा संघ की ओर से विशेष संदेश दिया गया। अंत में मूल निवासी अजय कुमार मांझी (राज्य अध्यक्ष मूल निवासी सभ्यता संघ, मध्यप्रदेश) द्वारा उपस्थित समस्त महानुभावों का आभार व्यक्त किया गया।

प्रस्तुति – शील बोधि
समन्वयक, भारतीय राष्ट्रीय
वाङ्मय संगीति

भारत के संविधान
भारतीय संविधान को समर्पित
मूलनिवासी
MULNIVASI SABHYATA SANGH
द्वितीय महासंगीति सांची
2nd MAHASANGITI SANCHI
25 से 27 अक्टूबर, 2025 (शनिवार, रविवार, सोमवार)
(Saturday, Sunday, Monday)
होटल संबोधि इंटरनेशनल, सांची, मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh
उद्घाटक
शैलेश नरवाडे,
मुख्य अतिथि
एड. गुरु प्रसाद मदन,
मू. सीमा बाबू सिंह वास्कले,
विशिष्ट अतिथि
मू. आर. एल. ध्रुव,
विशिष्ट उपस्थिति
मू. शर्मिष्ठा गौतम, मू. डॉ. नीलिमा बागडे,
मू. डॉ पी. कोमला, मू. हनीफ हंसलो
समारोह के अ
मू. सुनील कुमा

15 नवम्बर

के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं मंगल कामना

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक **पिंकी सत्यप्रेमी** ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार